(1)

B.A Part 2
IIIrd Paper

Dr. Om Prakash Kumar
Deptt. of economics
Patna Sahib College Patna

8.7.20

सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की भूमिका :- एक अध्ययन
(Role of agriculture in seventh & eighth five year plan)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि (agriculture in the seventh five year plan)

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में कृषि के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में कृषि-संबंधी कार्यक्रमों को ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन से जोड़ने की व्यवस्था थी। इसमें कृषि में वार्षिक 4% विकास का लक्ष्य निर्धारित था। सातवीं योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में वार्षिक 3.7% वृद्धि का आयोजन था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सातवीं योजना की अवधि में 110 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था थी। साथ ही, कृत्रिम खाद के उपयोग को 1984-85 में 84 लाख टन करने का आयोजन था। इसी प्रकार सुधरे हुए बीज की खपत को 70 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 107 लाख क्विंटल करने का आयोजन था। ~~जबकि उत्पादन 1730 लाख टन हुआ। योजना~~ योजनाकाल में खाद्यानों के उत्पादन को 1500 लाख टन से बढ़ाकर 1989-90 में 1780 से 1830 लाख टन का आयोजन था जबकि उत्पादन 1730 लाख टन हुआ। गन्ना के उत्पादन को 18 करोड़ टन से बढ़ाकर 21.7 करोड़ टन एवं जूट तथा कपास के उत्पादन को 75 लाख गाँठ तथा 79 लाख गाँठ हुआ। तलहन तथा दलहन के उत्पादन में और अधिक वृद्धि की व्यवस्था थी। सहकारिता तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख की मात्रा 1984-85 में 6810 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 12,750 करोड़ रुपये हो गयी।

सातवीं योजना काल में फसलों की बीमा (Crop Insurance) की व्यापक पद्धति को लागू करने, के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने तथा नियमित बाजारों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि का आयोजन था। इनके अतिरिक्त सातवीं योजना में पूर्वी राज्यों के लिए चावल उत्पादन तथा तिलहन के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम भी तैयार किया गया था। कृषि बीमा 18 राज्यों में लागू है तथा उन किसानों के लिए है जो सहकारी समितियों या बैंकों से कृषि कार्य के लिए कर्ज लेते हैं। प्रीमियम की दर चावल तथा गेहूँ के लिए २% दलहन एवं तेलहन के लिए 1% है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास की मद में वास्तविक व्यय 12,793 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम (Rural Development and Poverty Alleviation) पर 15,247 करोड़ रु तथा ग्रामीण विकास पर 15,246 करोड़ व्यय किया गया था। ~~जिनका विस्तृत विवरण~~ इसके अतिरिक्त सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण की मद में 16590 करोड़ रुपये व्यय किया गया था। इस प्रकार योजनाकाल में कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के मद में योजना के कुल व्यय के प्रायः 22% भाग व्यय का आयोजन था जबकि योजना में कृषि तथा सम्बंधित मदों में कुल 48,370 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो योजना के कुल व्यय का प्रायः 22% भाग था।

Scanned by CamScanner

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि
(Agriculture in Eighth five year Plan)

आठवीं योजना में कृषि के क्षेत्र में नियोजन का प्रधान उद्देश्य देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति के साथ-साथ निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में बचत करना था। साथ ही, औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कृषि से सम्बन्धित कच्चे पदार्थों की आपूर्ति बढ़ाने पर भी पर्याप्त जोर था। योजनाकाल में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि (Dry Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए नयी विधि को अपनाने पर जोर दिया गया था। आठवीं योजना में चावल, गेहूँ, बाजरा, तेलहन तथा दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए विस्तृत उत्पादन कार्यक्रम के आयोजन के साथ-साथ कपास के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने पर जोर था। आठवीं योजना में चावल के उत्पादन को 1991-92 के 275 लाख टन से बढ़कर 1996-97 में 880 लाख टन, गेहूँ के उत्पादन को 560 लाख टन से बढ़ाकर 660 लाख टन, दलहन के उत्पादन को 140 लाख टन से बढ़ाकर 170 लाख टन तथा कपास के उत्पादन को 105 लाख गाँठ से बढ़ाकर 140 लाख गाँठ करने का आयोजन था। आठवीं योजना में सभी खाद्यान्नों के उत्पादन को 1991-92 में 1725 लाख टन से बढ़ाकर 2100 लाख टन करने का आयोजन था।

Scanned by CamScanner

आठवीं योजना में कृषि तथा सिंचाई विकास पर 55,710 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 34425 करोड़ रुपये तथा विशेष कार्यक्रम पर 6510 करोड़ रु० व्यय का आयोजन था। इस प्रकार कृषि तथा ग्रामीण विकास पर योजना के कुल व्यय के 22% भाग व्यय का आयोजन था। योजनाकाल में अच्छी किस्म के बीज की आपूर्ति को 1991-92 में 41 लाख क्विंटल से बढ़कर 1996-97 में 110 लाख क्विं० खाद एवं उर्वरक के प्रयोग को 135 लाख टन से बढ़ाकर 143 लाख टन तथा कीटनाशक के प्रयोग को 80 हजार टन से बढ़ाकर 98 लाख हजार टन का करने का आयोजन था। साथ ही, सभी प्रकार के कृषि साख की मात्रा को 1991-92 में 5675 करोड़ की रु० रुपये से बढ़ाकर 1996-97 में 9290 करोड़ रुपये करने का आयोजन था। इस प्रकार आठवीं योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

Scanned by CamScanner